



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 591] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 1989/कार्तिक 16, 1911
No. 591] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 1989/KARTIKA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त संचालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों
और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989

सा.का.नि. 068 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम
अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी
(सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और
संशोधन करने के लिए नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम
विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन
नियम, 1989 है।]

(2) इसमें इनके पश्चात् अन्यथा उपरिष्ठित के सिवाय, इन नियमों
के उपबंधों को 1 अप्रैल, 1989 से लागू समझा जाएगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों
और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्
उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के स्थान पर नम्बितलिखित नियम
रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4. वेतनमान—

(1) विकास अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार
होंगे :—

1350-80-1750-100-1850-110-1900-ब.रो.-120-2920-
ब.रो.-120-3880 रु

(2) विकास अधिकारी को उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतन और
प्रतुल्य अन्य भत्ते कर्मचारिकान्त नियमों के विनियम 51 के अनुसार
विनियमित होंगे ;

(3) 1 अप्रैल, 1989 से, श्रेणी 2 के विकास अधिकारियों को
उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान के न्यूनतम पर रखा जाएगा।”

3. उक्त नियमों में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8. महंगाई भत्ता .

(1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :—

(क) सूचकांक औद्योगिक कर्मचारियों का अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक।

(ख) आधार : 1960=100 की शृंखला में सूचकांक संख्या 600

(ग) दर : महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 600 प्वाइंटों से ऊपर त्रैमासिक, औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंटों के बढ़ने या उनमें कमी आने के लिए त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। विकास अधिकारियों को महंगाई भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा :—

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ते की दर
(i) 1650 रु. तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत
(ii) 1651 से 2850 रु. तक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत धन 1650 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत।
(iii) 2851 रु. और उससे अधिक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत धन 2850 रु. और 1650 रु. के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत धन 2850 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.33 प्रतिशत।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निराशे औ (जिसे इसमें इसके पश्चात् “चालू औसत अंक” कहा गया है) में 600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600-604-608-612 और इसी अनुक्रम में प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर संश्लेष महंगाई भत्ते का उध्वगामी पुनरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता दिया गया है तो संश्लेष महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण होने पर, संश्लेष महंगाई भत्ता उस वृद्धि में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है, और यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संश्लेष महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है। इस प्रयोजन के लिए तिमाही से मार्च, जून, सितम्बर, या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास को अवधि अभिप्रेत होगी। भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में प्रकाशित अंतिम सूचकांक वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।

(3) किसी विशिष्ट मास के लिए महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए उस अंतिम तिमाही का त्रैमासिक औसत जिसके लिए अंतिम सूचकांक उस मास की 15 तारीख को उपलब्ध है, लिया जाएगा। इस पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का वास्तविक संश्लेष उस मास से अगले मास में किया जाएगा जिसमें सुवर्ण सूचकांक उपलब्ध हो।”

4. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6. मकान किराया भत्ता :

(1) विकास अधिकारियों को, सिवाय उनके जिन्हें निगम ने निवास स्थान प्रदान किया है मकान किराया भत्ता मापमान 3000 रु. के

मूल वेतन तक 12½ प्रतिशत की दर पर होगा और 3000 रु. से अधिक मूल वेतन के लिए 10 प्रतिशत की दर पर होगा किन्तु यह अधिक से अधिक 425 रु. प्रतिमास होगा।

(2) विकास अधिकारी, जिन्हें निगम द्वारा निवास स्थान प्रदान किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुमति फीस का संश्लेष करेंगे जिसका विनिश्चय निगम समय-समय पर करेगा और वे किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।”

6. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता .

विकास अधिकारियों को संश्लेष नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

तैनाती का स्थान	दर
(क) (1) वे नगर जिनकी आबादी मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, 165 रु. प्रतिमास से अधिक गाजियाबाद, नौएडा, पणजी और नहीं। मारमूगांव, 1 अप्रैल, 1988 से	
(2) मारमूगांव और पणजी से भिन्न मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु गोवा राज्य के किसी नगर में, 19 165 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं। मई, 1988 से	
(3) गुडगांव, वाशी और गांधी- मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु नगर में 12 मई, 1989 से 165 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।	
(ख) (1) वे नगर जिनकी आबादी मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियों जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पॉन्डिचेरी और पोर्ट ब्लेयर 1 अप्रैल, 1989 से	
(ii) पंचकुल नगर में, 12 मई, 1989 से मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 110 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।	

टिप्पणी : 1. इस नियम के प्रयोजनों के लिए आबादी के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना में दिए गए हैं।

2. नगरों के अर्थात् उनकी बस्तियां भी हैं।”

6. उक्त नियमों के नियम एक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7क. पर्वतीय स्थान भत्ता :

विकास अधिकारियों को देय पर्वतीय स्थान भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

(i) औसत समुद्र तल से 1,500 मूल वेतन के 7 प्रतिशत की दर मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर किन्तु 150 रु. प्रतिमास पर अवस्थित स्थान पर तैनात से अधिक नहीं।

- (11) अंशतः समुद्र तल से 1,000 मीटर और उससे ऊपर किन्तु 1,500 मीटर से कम ऊँचाई पर अवस्थित स्थानों पर सैनिक, मरकारा और ऐसे स्थाना पर तैनात जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है।

7. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) में "8½ प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ उनका प्रयोग किया गया है, "10 प्रतिशत" शब्द और शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (6) को खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) जहाँ किसी विकास अधिकारी पर प्रबंधन या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा से उत्पन्न किसी कार्य के लिए या नियोजन के स्थान में या उसके निकट किसी बलबाई या चिह्नकल व्यवहार के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अवैयक्तता अंतर्गुह्य हो, परन्तु तब जब ऐसा अपराध उसने अपने नियोजन के अनुक्रम में किया हो, पद-भुक्ति की शक्ति अधिरोपित की जाती है, वहाँ उसे देय अपमान पूर्णतः सन्पट्टित हो जाएगा।"

9. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"10. साम्प्रदायिक अनुतोष :

(1) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम कर्मचारियों के विनियम 51 के अन्तर्गत इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, विद्यमान विकास अधिकारियों का इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन 1 अप्रैल, 1989 से नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा और 1 अप्रैल, 1988 का प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए साम्प्रदायिक अनुतोष के रूप में नवतम की बढ़ावा राशि मंजूर कर सकेगा, जो उनके तथ्य वार्षिक परिलब्धियों और वार्षिक परिलब्धियों का भाग होगी :

परन्तु विकास अधिकारी इन नियमों के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर इस बात का पथन कर सकेगा कि उसके तबतन या उसके किसी भाग की ऐसी बढ़ावा उसकी तथ्य वार्षिक परिलब्धियों और 1 अप्रैल, 1989 के तुरन्त पश्चात् समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए वार्षिक परिलब्धियों का भाग होगी और उसका कोई अन्य अतिरिक्त उसके तुरन्त पश्चात् प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष का।

स्पष्टीकरण—

इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "विद्यमान विकास अधिकारी" पद से ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विकास अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(2) संवेष्टों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1989 को प्रारंभ होने वाले विद्यमान वर्ष की बचत संरक्षण उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक परिलब्धियों के भाग के रूप में होगी।

(3) निगम, कर्मचारियों के विनियम 51 के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अप्रैल, 1988 या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों

द्वारा यथा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त होने जाने को प्रभुति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्प्रदायिक अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम किन्ती और उसके निवन्धन और शर्तें क्या होंगी :

परन्तु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएँ विशेष उपबंधों के अधीन पर्यवसित की गई हैं साम्प्रदायिक अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जहाँ मूल वेतन ऐसे नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहाँ इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य बातों और फायदे भी ऐसे नियमों के आधार पर देय होंगे।"

[फा.सं. 2 (19)/बीमा-3/89]

एस. कानन, संयुक्त, सचिव

स्पष्टीकरण सापन

कैन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल 1989 से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तबनुसार नियमों की 1 अप्रैल 1989 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिभूतना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

3. मूल नियम अधिभूतना सं. सा.का.वि. 109 (अ) तारीख 17 सितम्बर 1986 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका संगीधन अधिभूतना सं. सा.का.वि. 960 (अ) तारीख 7 दिसम्बर 1987 और सा.का.वि. 871 (अ) तारीख 22-8-1986 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

INSURANCE DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1989

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA—
DEVELOPMENT OFFICERS (REVISION OF TERMS
AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT
RULES, 1989

G.S.R. 968(E):—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1989;

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1989.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said Rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Scale of pay:

(1) The scale of pay of the Development Officers shall be as follows : Rs. 1350-80-1750-100-1850-110-1960-EB-120-2920-EB-120-3880.

(2) The pay referred to in sub-rule (1) and other allowances admissible to a Development Officer shall be regulated in accordance with regulation 51 of the Staff Rules;

(3) With effect from the 1st day of April, 1989, Grade II Development Officer shall be placed at the minimum of the scale of pay referred to in sub-rule (1)."

3. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted namely:—

"5. Dearness Allowance :

(1) The scales of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Average Consumer Price Index number for Industrial Workers.

(b) Base: Index No. 600 in the Series 1960=100.

(c) Rate: Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall, in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 600 points. Development Officers may be paid dearness allowance at the following rates:—

Basic Pay	Rate of D.A. for every 4 points
(i) Upto Rs. 1650/-	0.67% of basic pay;
(ii) Rs. 1651/- to Rs. 2850/-	0.67% of Rs. 1650/- plus 0.55% of basic pay in excess of Rs. 1650/-;
(iii) Rs. 2851/- and above	0.67% of Rs. 1650/- plus 0.55% of difference between Rs. 2850/- and Rs. 1650/- plus 0.33% of basic pay in excess of Rs. 2850/-.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 600 points in the sequence 600-604-608-612 and so on and there shall be a downward revision of the dearness allowance payable if current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the 1st preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the above sequence. For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December. The final Index Figure as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the Index figure, which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(3) For the purpose of calculating dearness allowance for a particular month, the quarterly average for the last quarter for which the final index figures are available on the 15th day of that month shall be taken. Actual payment of this revised dearness allowance shall be made in the month following that in which the relevant index figures are available."

4. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. House Rent Allowance:

(1) The scale of house rent allowance of Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation shall be at the rate of 12½% of the basic pay upto Rs. 3000/- and at the rate of 10% of the basic pay which is in excess of Rs. 3000/-, subject to maximum of Rs. 425/- per month

(2) Development Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation shall pay for such residential accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Corporation from time to time and they shall not be entitled to any house rent allowance."

5. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. City Compensatory Allowance:

The scales of city compensatory allowance payable to Development Officers shall be as under:—

Place of Posting	RATE
(a) (i) Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Panaji and Marmugao on and from 1st day of April, 1988.	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per month.
(ii) Any city in the State of Goa, other than Panaji and Marmugao on and from 19th day of May, 1988.	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per month.
(iii) Cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar on and from the 12th day of May, 1989.	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per month.
(b) (i) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, state capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry and Port Blair on and from 1st day of April, 1988.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 110/- per month.
(ii) City of Panchkula on and from 12th day of May, 1989	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 110/- per month.

Notes: (1) For the purpose of this rule, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.
(2) Cities shall include their urban agglomerations."

6. In the said rules, for rule 7A, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. A-Hill Allowance:

The scales of hill allowance payable to Development Officers shall be as under:—

(i) Posted at places situated at a height of 1,500 metres and over above mean sea level. At a rate of 7% of the basic pay, subject to a maximum of Rs. 150/- per month.

- (ii) Posted at places situated at a height of 1,000 metres and above but less than 1,500 metres above mean sea level, at Merit 125/- per month "Hill Stations" specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.

7. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1), for the figures and words "8½ per cent" wherever it occurs, the figures and words "10 per cent" shall be substituted

8. In sub-rule (6) of rule 9 of the said rules, for clause (1) the following clause shall be substituted, namely -

- (1) Where the penalty of dismissal is imposed on a Development Officer for any act involving violence against the management or other employees or any riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment or for an offence involving moral turpitude provided that such offence is committed by him in the course of his employment, the gratuity payable to him shall stand wholly forfeited."

9. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely -

"10. Equitable Relief.

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, by instructions issued in this behalf under regulation 51 of the Staff Rules, provide for the fixation of basic pay of existing Development Officers in the scale of pay as revised by these rules, with effect from 1st day of April, 1988 and grant arrears of salary for the period commencing on the 1st day of April, 1988 and ending on 31st day of March, 1989 by way of equitable relief, which shall form part of their ad hoc annual remuneration and annual remuneration :

Provided that a Development Officer may, within 30 days of the publication of these rules, choose that such arrears of salary or any part thereof shall form part of his ad hoc annual remuneration and annual remuneration for the appraisal year ending immediately after the 1st day of April 1989, and, in respect of any balance thereof, for the appraisal year commencing immediately thereafter.

Explanation.

For the purpose of this sub-rule, the expression "existing Development Officers" means employees who are working as Development Officers on the date of publication of these rules

(2) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April, 1989 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year

(3) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under Regulation 51 of Staff Rules for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after 1st April, 1988, but before the date of publication of these rules, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payment by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and condition thereof

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the special provisions.

(4) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowance and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation".

[F.No. 2 (19)-Ins. III/89]

S. KANNAN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Development Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from 1st April, 1989. The rules are being amended accordingly with effect from 1st April, 1989

2 It is certified that no employee of Life Insurance Corporation is likely to be effected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Foot Note. The principal rules were published under Notification No. GSR/109 (E) dated 17-9-1986 and subsequently amended by GSR 962 dated 7-12-87 and GSR 871(E) dated 22-8-1988.

